भारत - आस्ट्रेलिया संबंध

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच अनेक समानताएं हैं जो उसी तर्ज पर जिसे भारत ने अन्य पश्चिमी देशों के साथ विकसित किया है, घनिष्ठ सहयोग एवं बहुआयामी अंत:क्रिया के लिए नींव के रूप में काम करती हैं। दोनों ही मजबूत, जीवंत, धर्मनिरपेक्ष एवं बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र हैं। दोनों देशों में प्रेस आजाद है तथा एक स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली है; अंग्रेजी भाषा एक महत्वपूर्ण कड़ी है। क्रिकेट तथा अब शिक्षा के लिए आस्ट्रेलिया आने वाले भारी संख्या में भारतीय छात्र लोकप्रिय स्तर पर जागरूकता में एक महत्वपूर्ण घटक है।

भारत आस्ट्रेलिया के विश्लेषण एवं नीति निर्माण में उत्तरोत्तर एक कारक बनता जा रहा है। हमारी बढ़ती आर्थिक प्रोफाइल तथा आस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था के लिए वाणिज्यिक प्रासंगिकता को आस्ट्रेलिया में राज्य एवं संघीय दोनों स्तरों पर स्वीकार किया गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिस्बेन, आस्ट्रेलिया में जी20 नेता शिखर बैठक की पूर्व संध्या पर नवंबर 2014 में आस्ट्रेलिया का दौरा किया था। जी20 शिखर बैठक की समाप्ति के बाद 16 से 18 नवंबर 2014 के दौरान उनकी यात्रा द्विपक्षीय यात्रा के रूप में थी।

भारत के साथ माल एवं सेवाओं में आस्ट्रेलिया का व्यापार 2014-15 में 13.565 बिलियन आस्ट्रेलियाई डालर (9.72 बिलियन अमरीकी डालर के समकक्ष) था जिसमें भारत द्वारा माल के निर्यात का हिस्सा 3.805 बिलियन आस्ट्रेलिया डालर (2.726 बिलियन अमरीकी डालर) था। भारत को आस्ट्रेलिया की ओर से माल का निर्यात 9.76 बिलियन आस्ट्रेलिया डालर (6.994 बिलियन अमरीकी डालर) था। इसके अलावा भारत ने 2.907 बिलियन आस्ट्रेलियाई डालर (2.083 बिलियन अमरीकी डालर) मूल्य की सेवाओं का निर्यात किया तथा भारत द्वारा सेवाओं के आयात का मूल्य 1.496 बिलियन आस्ट्रेलियाई डालर (1.072 बिलियन अमरीकी डालर) था। भारत के निर्यात गंतव्यों में आस्ट्रेलिया 33वें स्थान पर है तथा आयात के स्रोतों में यह 18वें स्थान पर है।

भारत द्वारा आस्ट्रेलिया को जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है उनमें मुख्य रूप से यात्री मोटर वाहन और मशीनरी, मोती, रत्न एवं आभूषण, शोधित पेट्रोलियम तथा वस्त्र शामिल हैं, जबकि भारत द्वारा आस्ट्रेलिया से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में सब्जियां, वूल, गैर मौद्रिक गोल्ड, कोयला, कापर और उर्वरक शमिल हैं।

दोनों देश इस समय एक व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (सी ई सी ए) पर चर्चा कर रहे हैं जो माल एवं सेवाओं के भारतीय निर्यातकों को अधिक बाजार पहुंच प्रदान करेगा। दोनों पक्षों ने सी ई सी ए के लिए माल एवं सेवाओं के लिए अपनी प्रस्ताव सूचियों का आदान प्रदान किया है। उम्मीद है कि सी ई सी ए पर निर्णय हो जाने से पण व्यापार के आधार का विस्तार होगा, गैर टैरिफ बाधाएं दूर होंगी, निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और व्यापार से जुड़ी

सीमा पारीय बाधाएं दूर होंगी। हम रत्न एवं आभूषण, फार्मास्युटिकल, यात्री कारों, जैविक रसायनों, परिवहन उपकरण, मशीनरी एवं अन्य उत्पादों के लिए विशिष्ट बाजार पहुंच के माध्यम से माल एवं सेवाओं में भारत के लिए प्रतिकूल व्यापार संतुलन का निदान भी करना चाहते हैं। सेवाओं के क्षेत्र में हम ग्रेटर मोड 4 अक्सेस तथा परस्पर मान्यता करार चाहते हैं। वार्ता के 9वें चक्र का आयोजन सितंबर 2015 में दिल्ली में हुआ था तथा 27 अक्टूबर को मंत्री रोब की यात्रा के दौरान इस पर आगे चर्चा होगी। नवंबर 2015 के लिए भारत आने और भारत में उद्योग / संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए आस्ट्रेलिया के उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए एक मेक इन इंडिया कार्यक्रम की योजना बनाई गई थी परंतु अब नई तिथियों पर विचार किया जा रहा है।

आस्ट्रेलिया में लगभग 4,50,000 का एक भारतीय समुदाय है जो शिक्षक, डॉक्टर, लेखाकार, इंजीनियर एवं शोधकर्ता के रूप में अपनी भूमिका के माध्यम से आस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहा है। आस्ट्रेलिया के लिए भारत उत्प्रवासियों का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है।

नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की आस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच पर्यटन के क्षेत्र में भी एक एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा एवं प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। आस्ट्रेलिया के नागरिकों के लिए गंतव्य के रूप में भारत का प्रचार प्रसार करने के लिए पर्यटन सप्ताह के साथ ही 2016 में आस्ट्रेलिया में भारत महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा।

भारत एवं आस्ट्रेलिया विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपस में सहयोग करते हैं। **आस्ट्रेलिया विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है।** भारत एवं आस्ट्रेलिया दोनों ही राष्ट्रमंडल, आई ओ आर ए, आसयिान क्षेत्रीय मंच, जलवायु एवं स्वच्छ विकास पर एशिया प्रशांत साझेदारी के सदस्य हैं तथा दोनों देशों ने पूर्वी एशिया शिखर बैठकों में भागीदारी की है। दोनों देश विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में पांच इच्छुक पक्षकारों (एफ आई पी) के सदस्य के रूप में भी आपस में सहयोग कर रहे हैं। **आस्ट्रेलिया अपेक में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है तथा इस संगठन में भारत की सदस्यता का समर्थन करता है।** 2008 में सार्क का प्रेक्षक बना।

विदेश मंत्री जूली बिशप ने नवंबर 2013 में और फिर अप्रैल 2015 में वार्षिक विदेश मंत्री रूपरेखा वार्ता के लिए भारत का दौरा किया। उन्होंने दिल्ली में ओ आर एफ को संबोधित करने के दौरान बताया कि विशेष रूप से भारत - प्रशांत सहयोग पर नवीकृत बल के संदर्भ में भारत के साथ अपने संबंधों को आस्ट्रेलिया कितना महत्व देता है।

पूर्व प्रधानमंत्री श्री टोनी एबाट ने हमारे प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 4 और 5 सितंबर 2014 को भारत का दौरा किया था। नई दिल्ली में श्री मोदी के नेतृत्व में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद यह पहली आवक राजकीय यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान असैन्य परमाणु

सहयोग, खेल, जल एवं कौशल पर चार करारों / एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए गए तथा अनेक महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एबाट ने नटराज और अर्ध नारीश्वर की दो चुराई गई प्रतिमाओं को सौंपा, जो आस्ट्रेलिया के संग्रहालयों में थीं।

व्यापार एवं निवेश मंत्री श्री एंड्रू रोब ने 450 से अधिक कारोबारी शिष्टमंडल के मुखिया के रूप में जनवरी 2015 में भारत का दौरा किया तथा वाइब्रेंट गुजरात शिखर बैठक में भी भाग लिया। वह सी ई सी ए पर निर्णय की प्रक्रिया को तेज करने के लिए पुन: अप्रैल 2015 के अंत में भारत के दौरे पर आए। श्री रोब ने भारत और आस्ट्रेलिया के सह अध्यक्षों के निमंत्रण पर पुनर्गठित भारत - आस्ट्रेलिया सी ई ओ फोरम में भाग लेने के लिए 2015 में तीसरी बार भारत का दौरा किया। श्री एंड्रू रोब ने भारत - आस्ट्रेलिया नेतृत्व शिखर बैठक के उद्घाटन सत्र के लिए एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ चौथी बार 25 से 27 अक्टूबर 2015 के दौरान भारत का दौरा किया।

भारत - आस्ट्रेलिया वरिष्ठ अधिकारी वार्ता (एस ओ टी) का आयोजन नई दिल्ली में 27 अक्टूबर को हुआ। आस्ट्रेलिया के शिष्टमंडल का नेतृत्व श्री पीटर वर्गीज, सचिव, डी एफ ए टी द्वारा किया गया तथा भारत के शिष्टमंडल का नेतृत्व श्री अनिल वाधवा, सचिव (पूर्व) द्वारा किया गया। पूर्वी एशिया तथा प्रशांत पर भारत - आस्ट्रेलिया वार्ता की चौथी बैठक अक्टूबर में कैनबरा में हुई।

एक कारोबारी शिष्टमंडल के साथ विद्युत, कोयला एवं प्राकृतिक ऊर्जा राज्य मंत्री ने 7 से 11 फरवरी के दौरान आस्ट्रेलिया का दौरा किया। उन्होंने तीन शहरों अर्थात ब्रिस्बेन, मेलबोर्न और सिडनी में ऊर्जा सुरक्षा तथा नवीकरणीय ऊर्जा के मुद्दों पर 5 गोलमेज में भाग लिया। उन्होंने कैनबरा का भी दौरा किया तथा व्यापार एवं निवेश मंत्री श्री एंड्रू रोब और संसाधन, ऊर्जा तथा उत्तरी आस्ट्रेलिया मंत्री जोश फ्राइडेनबर्ग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।

असैन्य परमाणु सहयोग का मुद्दा

जब प्रधानमंत्री एबाट सितंबर 2014 में भारत के दौरे पर आए थे तब दोनों देशों के बीच एक असैन्य परमाणु सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार को व्यवहार में लाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा आस्ट्रेलियाई संसद की संधियों पर संयुक्त चयन समिति द्वारा विस्तृत समीक्षा की जा रही है तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। भारत और आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने 15 नवंबर 2015 को अंताल्या में जी20 शिखर बैठक के दौरान अतिरिक्त समय में मुलाकात की तथा इस करार की पुष्टि की औपचारिक रूप से घोषणा की।

रक्षा सहयोग

पूर्व रक्षा मंत्री श्री ए के एंटोनी ने 4 से 5 जून 2013 के दौरान भारत के रक्षा मंत्री के रूप में आस्ट्रेलिया की पहली बार आधिकारिक यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने आस्ट्रेलिया के तत्कालीन रक्षा मंत्री स्टिफन स्मिथ के साथ पर्थ में वार्ता की और तत्कालीन प्रधानमंत्री सुश्री जुलिया गिलर्ड से शिष्टाचार मुलाकात की। अपनी बातचीत के दौरान दोनों रक्षा मंत्रियों ने रक्षा मंत्रियों के स्तर पर द्विपक्षीय वार्ता तथा सेना दर सेना वार्ता, रक्षा प्रशिक्षण तथा सेना प्रमुखों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की यात्राओं के आदान प्रदान की रूपरेखा के माध्यम से रक्षा संबंधों में तेजी से हुई प्रगति को स्वीकार किया। उन्होंने आपसी सरोकार के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की।

अक्टूबर 2013 में आस्ट्रेलिया की नौसेना ने सिडनी में एक अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा का आयोजन किया जिसमें भारतीय नौसेना के पोत आई एन एस सह्याद्री ने भाग लिया। भारतीय तटरक्षक पोत संकल्प ने दिसंबर 2014 के पहले सप्ताह में डार्विन बंदरगाह का दौरा किया तथा दो भारतीय जहाजों - आई एन एस सत्पुड़ा और आई एन एस कमोर्टा ने पूर्वी नौसेना कमान के मुखिया वाइस एडमिरल सतीश सोनी के नेतृत्व में सद्भावना यात्रा के रूप में जून 2015 के पहले सप्ताह में फ्रेंमंटल बंदरगाह, पर्थ का दौरा किया। इससे पूर्व राष्ट्रीय रक्षा कालेज के अधिकारियों के एक दल ने द्विपक्षीय रक्षा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत मई 2015 के आखिरी सप्ताह में आस्ट्रेलिया का दौरा किया था।

नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की आस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने अनुसंधान, विकास तथा औद्योगिक भागीदारी को शामिल करने के लिए रक्षा सहयोग का विस्तार करने का निर्णय लिया। वे रक्षा मंत्री के स्तर पर नियमित रूप से बैठकों का आयोजन करने, नियमित रूप से समुद्री अभ्यासों का आयोजन करने तथा सेना दर सेना वार्ता का नियमित रूप से आयोजन करने के लिए राजी हुए थे। चौथी वायु सेना दर वायु सेना वार्ता का आयोजन अप्रैल 2015 में कैनबरा में हुआ था तथा नौवीं वायु सेना दर वायु सेना वार्ता का आयोजन जून 2015 में सिडनी में हुआ था; चौथी थल सेना दर थल सेना वार्ता का आयोजन दिल्ली में होना है। चौथी रक्षा नीति वार्ता का आयोजन जून 2015 में कैनबरा में हुआ था। आस्ट्रेलिया के पूर्व रक्षा मंत्री श्री केविन एंड्रूज सितंबर 2015 के पूर्वार्ध में भारत के दौरे पर आने वाले हैं तथा हमारे सी एन एस एडमिरल आर के धवन ने द्विपक्षीय वार्ता के लिए अक्टूबर के पूर्वार्ध में आस्ट्रेलिया का दौरा किया तथा हवाइट शिपिंग सूचना विनिमय पर एक तकनीकी करार पर हस्ताक्षर किया।

पहली बार द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन विशाखापत्तनम में हुआ तथा बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना के युद्धक पोतों के साथ आस्ट्रेलिया की फ्रिगेट, पनडुब्बी, सपोर्ट शिप तथा पी3 समुद्री निगरानी एयरक्राफ्ट ने भाग लिया। दोनों पक्षों ने अभ्यास के आयोजन पर संतोष प्रकट किया तथा इसे एक द्विवार्षिक कार्यक्रम बनाने के लिए राजी हुए।

जून 2015 में जापान के साथ पहली सचिव स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता में तथा 2016 के पूर्वार्ध से वार्षिक सचिव स्तरीय 2 प्लस 2 वार्ता के आयोजन के लिए निर्णय में भी घनिष्ठ सामरिक सहयोग स्पष्ट है।

कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत - आस्ट्रेलिया सामरिक अनुसंधान निधि (ए आई एस आर एफ) स्थापित की गई है; दोनों देशों ने इन क्षेत्रों में सहयोग के लिए अनेक अनुसंधान परियोजनाओं की पहचान की है। इस निधि के तहत सहयोग के लिए जो क्षेत्र शामिल हैं वे इस प्रकार हैं : कृषि अनुसंधान, ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, सूक्ष्म इलेक्ट्रानिक्स, नैनो प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री विज्ञान तथा पृथ्वी प्रणाली विज्ञान।

इस समय 5 वर्ष की अवधि में प्रत्येक पक्ष से ए आई एस आर एफ की राशि 65 मिलियन आस्ट्रेलियाई डालर है। यह निधि ऊर्जा, खाद्य तथा जल सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर केन्द्रित व्यावहारिक समाधान प्रदान करने के लिए तैयार की गई बृहद अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करती है। ए आई एस आर एफ के तहत भारत - आस्ट्रेलिया जैव प्रौद्योगिकी निधि; भारत - आस्ट्रेलिया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निधि; महान चुनौती निधि एवं फेलोशिप स्कीमें शामिल हैं। यह उपर्युक्त क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान की सहायता के लिए दोनों पक्षों द्वारा पहले प्रतिबद्धता किए गए 40 मिलियन डालर तथा भारत में शुष्क भूमि कृषि में संयुक्त अनुसंधान करने के लिए आस्ट्रेलियाई अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र (ए सी आई ए आर) के लिए 20 मिलियन डालर के अलावा है। इस निधि के प्रशासन के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी पर संयुक्त समितियां स्थापित की गई हैं। हमारे प्रधानमंत्री की आस्ट्रेलिया की हाल की यात्रा के दौरान हुई सहमति के अनुसार आस्ट्रेलिया हमारी स्वच्छ गंगा परियोजना में भी सहयोग करेगा।

संसाधन

ऊर्जा एवं संसाधन क्षेत्र में हमारे संबंध का विस्तार करने के लिए 1999 में ऊर्जा एवं खनिज पर एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया था। ऊर्जा एवं खनिज पर संयुक्त कार्य समूह की 7वीं बैठक 17 और 18 मई 2011 को सिडनी में हुई थी। भारत के खान मंत्रालय तथा आस्ट्रेलिया के संसाधन, ऊर्जा एवं पर्यटन विभाग के बीच 2011 से 2014 के लिए खनन एवं खनिज कार्य योजना के तहत एक कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए। संयुक्त कार्य समूह की 8वीं बैठक जून 2013 में दिल्ली में हुई थी जिसमें व्यापार एवं निवेश, ऊर्जा एवं खनिज निधि के क्षेत्र में हाल की उपलब्धियों तथा दोनों देशों में संसाधनों की आवश्यकता एवं उपलब्धता पर चर्चा हुई। संयुक्त कार्य समूह ने 5 कार्य योजनाओं अर्थात खनन एवं खनिज, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कोयला, विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा में से प्रत्येक के तहत 2013 से 2015 के बीच गतिविधियों की एक नई कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। जैसा कि ऊर्जा आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, हमारे प्रधानमंत्री की नवंबर

2015 में आस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों पक्ष स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी में सहयोग करने के लिए राजी हुए तथा भारतीय खान विद्यालय, धनबाद के उन्नयन के लिए आस्ट्रेलिया की इच्छा का स्वागत किया गया। जून 2015 में ब्रिस्बेन में आयोजित संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक के दौरान इन पर और चर्चा हुई।

अडानी इंटरप्राइजेज, जो भारत का सबसे बड़ा कोयला आयातक है, ने 500 मिलियन डालर प्लस रॉयल्टी के बदले में लिंक एनर्जी के क्विंसलैंड कोल परमिट में से एक को खरीदने के लिए करार किया है। लिंक ने 20 वर्षों में 3 बिलियन डालर मूल्य के एक सौदे में अडानी ग्रुप को अपना गैलिली बेसिन कोल डिपाजिट बेचा है। अडानी ने 1.83 बिलियन आस्ट्रेलियाई डालर की लागत से 99 साल की अवधि के लिए एबाट प्वाइंट कोल लोडिंग टर्मिनल के प्रबंधन का अधिकार भी प्राप्त किया है। उन्होंने क्विंसलैंड में कार्मीकेल खान में कोयला खनन अन्वेषण का सबसे बड़ा कार्यक्रम पूरा किया है तथा 16 बिलियन डालर मूल्य की अपनी परियोजना शुरू करने के लिए तैयार है, जिसमें एक विश्व स्तरीय खान, रेल और बंदरगाह अवसंरचना का निर्माण शामिल होगा। दुर्भाग्य से पर्यावरणीय समूहों द्वारा इस परियोजना का दृढ़ता के साथ विरोध किया जा रहा है जिससे समस्याओं के निदान के लिए सरकार की ओर से सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद प्रक्रियाओं में कई तरह के विलंब हो रहे हैं।

जी वी के पावर एंड इनफ्रास्क्ट्रचर ने 18.89 मिलियन आस्ट्रेलियाई डालर के बदले में सितंबर 2012 में पर्थ आधारित लिगेसी आयरन ओर में आस्ट्रेलिया की हैंड कॉक प्रास्पेक्टिंग से दो थर्मल कोल माइन खरीदने के कार्य को अंतिम रूप दिया था। एन एम डी सी भी एटलस आयरन ओर की रिडले मैग्निटी प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए समुचित अध्यवसाय का आयोजन कर रहा है।

शिक्षा

दोनों देशों के बीच शिक्षा पर संयुक्त कार्य समूह ने सहयोग के लिए अनेक प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है जिसमें शिक्षा नीति में सहयोगात्मक अनुसंधान, छात्र विनिमय कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा में क्षमता निर्माण तथा उच्च शिक्षा में दूरस्थ अध्ययन शामिल हैं। इस समय आस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 46000 के आसपास है जिसमें से 50 प्रतिशत छात्र उच्च शिक्षा में हैं तथा शेष छात्र व्यावसायिक एवं शैक्षिक प्रशिक्षण में हैं।

आस्ट्रेलिया के उच्च शिक्षा मंत्री सिनेटर किम कार के साथ वार्षिक शिक्षा मंत्री वार्ता का आयोजन करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री डा. एम पल्लम राजू ने 9 से 12 जुलाई 2013 के दौरान आस्ट्रेलिया का दौरा किया। इस अवसर पर दूसरा भारत - आस्ट्रेलिया वाइस चांसलर सम्मेलन भी आयोजित किया जिसमें भारत - आस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय साझेदारी तथा भारत - आस्ट्रेलिया उद्योग / सेक्टर कौशल परिषद साझेदारी की समीक्षा की गई। भारत - आस्ट्रेलिया शिक्षा परिषद की तीसरी बैठक के लिए अगस्त 2015 में श्री क्रिस्टोफर

पाइन ने भारत का दौरा किया। उनके साथ इस दौरे पर 40 वाइस चांसलर, शिक्षाविद और वरिष्ठ अधिकारी भी आए थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने मुंबई में संयुक्त आई आई टी बाम्बे - मोनाश विश्वविद्यालय कैंपस का भी उद्घाटन किया।

नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की आस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने भारत और आस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग, विशेष रूप से अनुसंधान को प्रोत्साहित करने, स्कूल स्तरीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त पी एच डी कार्यक्रम का स्वागत किया जिसके तहत आस्ट्रेलिया की टीम भारत के 5 से 7 राज्यों में आकर अध्ययन कर सकती है और विश्वविद्यालयों के बीच अनुबंधों को प्रोत्साहित कर सकती है। आस्ट्रेलिया भारत में एक विश्व स्तरीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने में मदद करने के लिए भी राजी हुआ है।

आस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय

आस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय तेजी से बढ़ रहा है जिसकी संख्या 4,50,000 के आसपास है जो शिक्षक, डॉक्टर, लेखाकार, इंजीनियर एवं आई टी इंजीनियर के रूप में अपनी भूमिका के माध्यम से आस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में काफी योगदान कर रहा है। आज यू के और न्यूजीलैंड के बाद आस्ट्रेलिया के लिए भारत प्रवासियों का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है तथा आस्ट्रेलिया के लिए यू के बाद कुशल प्रोफेशनल का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। इसके अलावा फिजी, मलेशिया, कीनिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से भारतीय मूल के व्यक्तियों की अच्छी खासी संख्या है।

कोंसुलर सहयोग

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच परस्पर कानूनी सहायता संधि (एम एल ए टी) तथा प्रत्यर्पण संधि, जिस पर जून 2008 में हस्ताक्षर किए गए थे, की दोनों देशों की सरकारों द्वारा पुष्टि की गई है तथा 20 जनवरी 2011 से लागू हो गए हैं।

सितंबर 2008 में विदेश मंत्री श्री स्टिफन स्मिथ की भारत यात्रा के दौरान वीजा, पासपोर्ट और कोंसुलर मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह (जे डब्ल्यू जी) का गठन किया गया था। कोंसुलर, पासपोर्ट तथा वीजा मामलों पर भारत - आस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक अगस्त 2014 के अंत में कैनबरा में हुई थी। संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक 20 और 21 अक्टूबर 2015 को कैनबरा में हुई।

नवंबर 2014 में हमारे प्रधानमंत्री की आस्ट्रेलिया यात्रा की पूर्व संध्या पर भारत और आस्ट्रेलिया द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार के शीघ्र ही

लागू हो जाने की उम्मीद है जिससे आस्ट्रेलिया में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों को लाभ होगा।

उपयोगी संसाधन :

भारतीय उच्चायोग, कैनबरा की वेबसाइट :
www.hcindia-au.org

***

फरवरी, 2016